RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 02
अंक : 003
दि. 03.05.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

होर्मुज बनेगा कब्रिस्तान! अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खतरनाक इरादों पर ईरान ने दी 'परमाणु' चेतावनी

(जीएनएस)।

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए जाने के बाद ईरान की सेना ने 'महायुद्ध' की चेतावनी दी है। ईरान का मानना है कि अमेरिका किसी भी संधि को मानने के लिए तैयार नहीं है और केवल दबाव बनाने की राजनीति कर रहा है।

ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को कमजोर और बिखरा हुआ बताया है, जबकि ईरान ने पलटवार करते हुए कहा है कि उनकी सेना किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मोहम्मद जाफर असादी ने कहा है कि अमेरिका के बयान केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने और तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हैं। उन्होंने साफ किया कि ईरान की सेना हाई अलर्ट पर है। असादी के मुताबिक, अगर अमेरिका ने कोई भी "मूर्खतापूर्ण" कदम उठाया या हमला करने की कोशिश की, तो ईरान उसे करारा जवाब देगा। ईरान का कहना है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद रखने के अपने फैसले पर अडिग है।

तनाव के बीच ईरान में एक दुखद हादसा हुआ है, जहां पुराने बमों के फटने से रिवोल्यूशनरी गार्ड (क्य्र्क्ष्) के 14 जवानों की जान चली गई। यह विस्फोट तेहरान के पास जंजन शहर में हुआ। बताया जा रहा है कि ये बम पुराने युद्ध के समय के थे जो फटे नहीं थे। 7 अप्रैल को हुए युद्धविराम के बाद ईरानी सेना के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है, जिससे देश के अंदर शोक और गुस्से का माहौल है।

सख्त चेतावनी और सैन्य विकल्प

राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ईरान के साथ मौजूदा बातचीत के प्रस्तावों से खुश नहीं हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ईरान का नेतृत्व आपस में बंटा हुआ है और उन्हें खुद नहीं पता कि उनका असली नेता कौन है। ट्रंप के अनुसार, ईरान की नौसेना और वायुसेना अब बहुत कमजोर हो

चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ, तो वह सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे और इसके लिए उन्हें संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर बना टकराव

इस पूरे विवाद की जड़ में होर्मुज स्ट्रेट है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान इस समुद्री रास्ते को खुला रखे ताकि दुनिया भर में तेल की सप्लाई बिना रुके चलती रहे। इसके उलट, ईरान इसे खोलने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने इसे लेकर युद्धविराम जारी रखने की शर्त भी रखी है, लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिका समझौतों का सम्मान नहीं करता। दोनों देशों के बीच यह अड़ियल रुख आने वाले दिनों में बड़े संघर्ष का कारण बन सकता है।

'काम के बदले देना होगा दाम. वरना सरकार करेगी काम तमाम', मजदूर दिवस पर सीएम योगी का कड़ा अल्टीमेटम

लखनऊः (जीएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 'श्रमवीर गौरव समारोह 2026' में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के मजदूरों और कामगारों के हितों को लेकर अब तक का सबसे सख्त संदेश दिया है।

सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में कहा कि श्रमिकों के अधिकारों के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "काम के बदले दाम देना ही होगा, अन्यथा सरकार ऐसे लोगों का काम तमाम करने में देर नहीं करेगी।"

श्रमिकों को मिला सम्मान और योजनाओं की सौगात

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए कुशल श्रमिकों को प्रमाणपत्र और टूलकिट बांटकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि प्रदेश के सभी 75 जिलों से चुने गए 75 श्रमिकों में से 5 को मंच पर बुलाकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, अटल आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले होनहार छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिए गए और प्रयागराज व झांसी के स्कूलों के प्रिंसिपल्स को भी उनके बेहतर काम के लिए सम्मान मिला।

उत्तर प्रदेश अब बना 'उद्यम प्रदेश'

अपने संबोधन में सीएम योगी ने यूपी की बदलती तस्वीर का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश 'उद्यम प्रदेश' के रूप में देश की अर्थव्यवस्था का असली 'ग्रोथ इंजन' बन चुका है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि साल 1947 से 2017 के बीच प्रदेश में सिर्फ 14 हजार उद्योग लगे थे, लेकिन 2017 के बाद से अब तक रिकॉर्ड 18 हजार से ज्यादा नए उद्योग स्थापित हुए हैं। इन नए उद्योगों की वजह से लाखों नौजवानों को अपने ही घर में रोजगार के मौके मिल रहे हैं।

विपक्ष पर निशाना और कोरोना काल की याद

कोरोना काल की चुनौतियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब संकट का समय था और कई नेता गायब थे, तब सरकार ने आगे बढ़कर श्रमिकों के लिए काम किया। प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर लाने के लिए हजारों बसें चलाई गईं और उनके खाने-पीने का मुफ्त इंतजाम किया गया। सीएम ने याद दिलाया कि मुफ्त राशन की जो सुविधा तब शुरू हुई थी, वह आज भी करोड़ों परिवारों को मिल रही है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर बड़ा फोकस

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि गरीबों और मजदूरों के हक पर डाका डालने वालों की अब खैर नहीं है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय किसी वरदान से कम नहीं हैं, जहां उन्हें हाई-टेक और क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। साथ ही, उन्होंने नोएडा के जेवर में श्रमिकों के बच्चों के लिए एक नए कंपोजिट स्कूल की आधारशिला रखने का भी ऐलान किया।

स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे पर सीएम योगी ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है और जो श्रमिक अभी तक छूट गए हैं, उनके भी जल्द आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके अलावा, किसी दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर देने की भी तैयारी सरकार कर रही है। आवास और स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों को पक्का घर और शौचालय मिलने से उनके जीवन स्तर में

'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी' कर रहे विशेष ध्यान', गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- 2019 के बाद तेजी से बदली लद्दाख की तस्वीर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होने के बाद लद्दाख तेजी से बदलाव का मॉडल बन गया है,

पीटीआई, लेह। (जीएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होने के बाद लद्दाख तेज बदलाव का माडल बन गया है। उन्होंने लद्दाख दौरे के दौरान क्षेत्र में व्यापक राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों को लोगों के सामने रखा।

यह क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के विकास एजेंडे के केंद्र में बना हुआ है। विकास में हो रहे भेदभाव के कारण लद्दाख में लंबे समय से अलग प्रदेश की मांग की जा रही थी। उनकी यह टिप्पणी लेह एपेक्स बाडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा राज्य के दर्जे और लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के बीच आई है।

लद्दाख में अब पांच नए जिले बनाए गए हैं और इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। स्थानीय भाषाओं को भी प्रशासनिक मान्यता दी गई है। अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भोटी, पुर्गी और उर्दू को महत्व दिया है।

उन्होंने बुनियादी ढांचे की मजबूती को उजागर करते हुए कहा कि लद्दाख में सड़क की लंबाई 2019 से पहले 1,799 किलोमीटर थी और छह वर्ष में यह दोगुनी से अधिक बढ़कर 4,040 किलोमीटर हो चुकी है। पुलों की संख्या तीन गुणा बढ़ गई है।

शाह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का ध्यान लद्दाख पर केंद्रित रहा है और लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। एक समय जोजि ला पास वर्ष में 127 दिन तक बंद रहता था, इस वर्ष केवल 19 दिन के लिए बंद रहा। लद्दाख 2024 में साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गया और दावा किया कि क्षेत्र में कोई भी निरक्षर व्यक्ति नहीं बचा है।

संक्षिप्त समाचार

बंगाल में स्ट्रॉन्ग रूम विवाद के बाद चुनाव आयोग का एक्शन, 6 अधिकारी सस्पेंड

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले ईवीएम (EVM) की सुरक्षा को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। स्ट्रॉन्ग रूम को अनधिकृत तरीके से खोलने के मामले में निर्वाचन आयोग (एउ) ने कड़ा रुख अपनाते हुए 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें बिधाननगर के डिप्टी मजिस्ट्रेट गौतम मंडल भी शामिल हैं। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बिधाननगर और डायमंड हार्बर क्षेत्र में बीजेपी नेताओं ने स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा में चूक पकड़ी। बीजेपी नेता डॉ. शरदवत मुखोपाध्याय ने ढळक से बातचीत के दौरान गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, 'हमें स्ट्रॉन्ग रूम खोलने का जो समय दिया गया।

छत्तीसगढ़ के कांकेर में आईईडी डिफ्यूज करते वक्त 3 जवान शहीद, देश के 'नक्सल मुक्त' घोषित होने के बाद बड़ी वारदात

(जीएनएस)।

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। नक्सलियों द्वारा जमीन के नीचे छिपाए गए एक पुराने बम (IED) को डिफ्यूज करते समय हुए धमाके में पुलिस के तीन जवान शहीद हो गए हैं। शहीदों में एक इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब जवान इलाके को सुरक्षित करने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे थे।

बस्तर रेंज के आईजी पी. सुंदरराज. ने बताया कि यह घटना कांकेर जिले के छोटेबेटिया थाना क्षेत्र के जंगलों में हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सलियों ने पहले यहां बड़ी संख्या में बम प्लांट किए थे। इसी जानकारी के आधार पर डीआरजी (DRG) की टीम 'डीमाइनिंग ऑपरेशन' पर निकली थी।

जवानों ने एक आईईडी खोज भी लिया था, लेकिन जैसे ही वे उसे डिफ्यूज यानी निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे, अचानक उसमें जोरदार धमाका हो गया।

हादसे में इन्होंने गंवाई जान

धमाका इतना शक्तिशाली था कि चार जवान इसकी चपेट में आ गए। पुलिस के मुताबिकः

इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी (मौके पर ही शहीद)

कांस्टेबल कृष्ण कोमरा (मौके पर ही शहीद)

कांस्टेबल संजय गढ़पाले (मौके पर ही शहीद)

एक अन्य जवान परमानंद कोमरा इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ट्वीट कर इस घटना पर गहरा दुख जताया। सीएम ने लिखा, 'कांकेर-नारायणपुर सीमा क्षेत्र में डीमाइनिंग अभियान के दौरान क्एऊ विस्फोट में DRG के तीन वीर जवानों के शहीद होने तथा एक जवान के घायल होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ।'

उन्होंने आगे लिखा, 'शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा घायल जवान के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें।

अब आरएसएस और पीएम मोदी के बारे में भी होगी पढ़ाई, शुरू हुआ नया कोर्स

महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय ने एक नया पाठ्यक्रम शुरू

(जीएनएस)।

वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय ने एक नया कोर्स शुरू किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बारे में पढ़ाया जाएगा. आर्ट्स फैकल्टी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में शुरू हुए 'मोदी तत्व' कोर्स में सिर्फ पीएम मोदी की लीडरशिप के बारे में ही नहीं पढ़ाया जाएगा बल्कि सोशियोलॉजी पेट्रियॉटिज्म सब्जेक्ट में 'फ्रर को जानें' भी पढ़ाया जाएगा.

वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय (MSU) ने अपने पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस (RSS) के इतिहास और वर्तमान प्रशासन के मूल सिद्धांतों पर कोर्स

शुरू किया गया है. नई शैक्षणिक संरचना के तहत, समाजशास्त्र विभाग के छात्रों को अपने मुख्य पाठ्यक्रम में इन विषयों का अध्ययन करना अनिवार्य होगा. विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को समकालीन वैचारिक आंदोलनों और राष्ट्र की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है, जो संस्थान की शिक्षण दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है.

अगर सरल शब्दों में कहें तो वडोदरा की इस MS यूनिवर्सिटी में आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें फ्रर की आइडियोलॉजी और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के बारे में बताया जाएगा.

यह कोर्स आर्ट्स फैकल्टी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में शुरू किया गया है. इस 'मोदी तत्व' कोर्स में नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी और लीडरशिप के बारे में पढ़ाया जाएगा.

हरियाणा के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से भेंट की

हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट

किया:

"हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने प्रधानमंत्री @narendramodi से भेंट की।"

लेह में 'तथागत के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी' के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने प्रसन्नता जताई

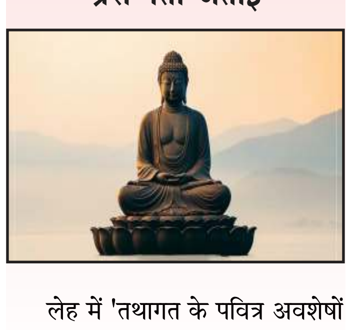

लेह में 'तथागत के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी' के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने प्रसन्नता जताई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि कल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लेह में 'तथागत के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी' का उद्घाटन किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये पूजनीय अवशेष कपिलवस्तु के पिपरावा स्तूप से संबंधित हैं और उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उत्खनित किए गए थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रदर्शनी लद्दाख के लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करती है।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सीएम योगी को लिखा पत्रः एनसीआर में श्रमिकों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त

(जीएनएस)।

लखनऊ, 2 मई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच ने एक विस्तृत पत्र लिखकर औद्योगिक क्षेत्रों, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में काम कर रहे श्रमिकों की बदतर स्थिति का मुद्दा उठाया है। पत्र में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी, लंबे काम के घंटे, सुरक्षा, यूनियन अधिकार और पुलिस कार्रवाई जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने की मांग की गई है।

पत्र में कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों से न्यूनतम मजदूरी में कोई संशोधन नहीं किया गया है, जबकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान हैं। महंगाई के कारण जरूरी वस्तुओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे श्रमिकों का जीवन और कठिन हो गया है।

ट्रेड यूनियनों ने आरोप लगाया कि कई औद्योगिक इकाइयों में कार्यस्थल पर सुरक्षा के न्यूनतम उपाय भी नहीं किए जा रहे हैं। श्रमिकों को बिना ओवरटाइम भुगतान के 12-13 घंटे काम करने को मजबूर किया जाता है। महिला श्रमिकों सहित श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें आम हैं।

कार्यस्थलों पर बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, पीने का पानी और विश्राम कक्ष तक उपलब्ध नहीं हैं। छुट्टियों के प्रावधानों की भी अनदेखी हो रही है।

पत्र में सबसे गंभीर मुद्दा यह उठाया गया है कि श्रमिकों को यूनियन बनाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यदि कोई श्रमिक यूनियन बनाने का प्रयास करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिए जाने का खतरा रहता है। सामूहिक सौदेबाजी की पूरी तरह अनुपस्थिति से श्रमिकों में हताशा और निराशा बढ़ रही है।

ट्रेड यूनियनों ने आरोप लगाया कि जब श्रमिकों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं तो प्रशासन ने उनके नेताओं को नजरबंद कर दिया। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों पर पुलिस द्वारा अत्याचार, गिरफ्तारियां और कड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। महिला श्रमिकों का अपमान भी किया गया। कई परिवार अपने गिरफ्तार सदस्यों का पता लगाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं और जमानत याचिकाएं भी खारिज हो रही हैं।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया है कि वे श्रमिकों के प्रति नरम रुख अपनाएं, गिरफ्तार श्रमिकों को रिहा करवाएं और उनके परिवारों को राहत दें। उन्होंने कहा कि औद्योगिक अशांति का कारण श्रमिक नहीं, बल्कि नियोक्ताओं द्वारा कानूनों का पालन न करना है। यूनियनों ने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से न्यूनतम मजदूरी समिति या बोर्ड का गठन किया जाए, जिसमें वैज्ञानिक आधार पर मजदूरी तय की जा सके।

सम्पादकीय

खाड़ी देशों में आपसी मतभेद तेजी से बढ़ते नजर आने लगे

अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद से खाड़ी देशों में आपसी मतभेद तेजी से बढ़ते नजर आने लगे हैं। होर्मूज स्ट्रेट के बंद होने से स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। इस रास्ते के बंद होने से खाड़ी के बड़े देश जिनकी अर्थव्यवस्था तेल के निर्यात पर निर्भर है वह खासे उत्तेजित हैं। इसका एक नतीजा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का प्रमुख तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर जाने का पैसला। यह पैसला ईरान जंग की वजह से ऐतिहासिक रूप से दुनियाभर में ऊर्जा को लेकर एक बड़ा संकट पैदा हुआ है और जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। यूएई ने कहा है कि यह पैसला उसकी दीर्घकालिक रणनीति इकोनॉमिक विजन और बदलती एनजी प्रोफाइल को दशार्ती है। यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहैल मोहम्मद अल मजरूई ने कहा है कि इस समूहों के तहत किसी बाध्यता से मुक्त होने पर देश को ज्यादा लचीलापन मिलेगा। ओपेक को 60 साल बाद छोड़ने का पैसला यूएई ने अचानक नहीं लिया, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से पनप रहा असंतोष है। अबू धाबी को लगातार यह खटक रहा था कि सऊदी अरब ओपेक के जरिए तेल उत्पादन को नियंत्रित करता है और यूएई को अपनी क्षमता के हिसाब से ज्यादा तेल निकालने नहीं देता। जब यूएई ज्यादा उत्पादन करना चाहता था, तब सऊदी कम उत्पादन पर जोर देता रहा, जिससे दोनों देशों में तनाव बढ़ता चला गया। इस तनाव को हवा और तब मिली जब पाकिस्तान की भूमिका सामने आई। यूएई को पाकिस्तान का रवैया बिल्वुल पसंद नहीं आया, खासकर तब जब अमेरिका और ईरान के बीच वह मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा था। एमएसटी फाइनेंशियल में ऊर्जा अनुसंधान के प्रमुख शाऊल कावर्निक ने कहा कि यह गठबंधन के अंत की शुरूआत हो सकती है। यूएई के जाने के साथ ओपेक अपनी क्षमता का लगभग 15 प्रतिशत खो देगा। इस पैसले को ओपेक के साथ-साथ इस गुट के सर्वेसर्वा माने जाने वाले सऊदी अरब के लिए झटका माना जा रहा है। यूएई का बाहर जाना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक जीत माना जा रहा है जिन्होंने पहले ओपेक पर दुनिया का शोषण करने का आरोप लगाया था। जनवरी में उन्होंने सऊदी अरब और अन्य ओपेक देशों से तेल की कीमत कम करने को कहा था और टैरिफ लगाने की अपनी धमकी को भी दोहराया था। यूएई का ओपेक से अलग होने का निर्णय सिर्प एक सदस्य देश का प्रस्थान नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक अहम मोड़ है। यह पैसला ऐसे समय आया है, जब पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव, होर्मूज जलडमरूमध्य पर अनिश्चितता और वैश्विक मुद्रास्फीति पहले से ही तेल बाजार को अस्थिर बनाए हुए है। यूएई ओपेक का तीसरा बड़ा उत्पादक सदस्य देश था और समूह के उत्पादन में करीब 12 फीसदी का योगदान करता था। ऐसे में उसका बाहर निकलना ओपेक की आपूर्ति क्षमता को प्रभावित जरूर करेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर ओपेक की शतरे से मुक्त यूएई वैश्विक तेल बाजार को अतिरिक्त आपूर्ति करता है तो इससे तेल की कीमतों में कमी आ सकती है। यह स्थिति भारत जैसे उन देशों के लिए विशेष तौर पर फायदेमंद है जो ऊर्जा के आयात पर ही निर्भर है। गौरतलब है कि भारत अपने ऊर्जा सुरक्षा संबंधी तथ्यों से निपटने के लिए लंबे समय से ओपेक देशों से तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी करने की मांग करता रहा है। भारत का वुल तेल जरूरतों का लगभग 40 फीसदी हिस्सा ओपेक देशों से आता है। हालांकि यह देखते हुए कि वैश्विक ऊर्जा बाजार कभी स्थिर नहीं रहता, वह निरंतर भू-राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय बदलावों से प्रभावित होता रहता है।

अतंर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 के आयोजन से 50 दिन पहले 6,000 लोगों ने भुजंगासन कर एशिया रिकॉर्ड बनाया

योग महोत्सव में वैश्विक भागीदारी: 20 से अधिक देशों ने

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के आयोजन से पहले योग महोत्सव में भाग लिया

'योग – 2047 तक एक स्वस्थ और अनुशासित विकसित भारत के निर्माण की कुंजी ': केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी

'हैदराबाद को योग और स्वास्थ्य देखभाल के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरना चाहिए ': श्री रेड्डी।

'योग स्वास्थ्य और कल्याण के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की पहचान को मजबूत करता है ': केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव

'योग 365 अभियान नागरिकों को योग के प्रतिदिन अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करता है ': श्री प्रतापराव जाधव

(जीएनएस)।

मोतियों की नगरी हैदराबाद में योग महोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन हुआ जिसमें हजारों उत्साही लोग एकत्रित हुए। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के मुख्य आयोजन से 50 दिन पहले के कार्यक्रम से जुड़ा था। आयुष मंत्रालय के अधीन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम शांत आध्यात्मिक केंद्र, कान्हा शांति वनम में हुआ।

कान्हा शांति वनम में 6000 से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ भुजंगासन का अभ्यास किया जिससे एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना और यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई क्योंकि इस आयोजन को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक साथ आसन करने वाले सबसे बड़े समूह के रूप में दर्ज किया गया। यह योग के माध्यम से प्रचारित सामूहिक भागीदारी और साझा कल्याण की भावना को दशार्ता है।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी उपस्थित थे। श्री रेड्डी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, 'योग केवल भारत की प्राचीन विरासत ही नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक अनमोल उपहार है। आज विश्वभर में नेता, पेशेवर और आम लोग योग का अभ्यास करते हैं और इससे लाभ उठाते हैं।'

उन्होंने राष्ट्र निर्माण में योग की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'भारत को 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए एक स्वस्थ, शांतिपूर्ण और अनुशासित समाज का निर्माण करना होगा। योग तनाव, अस्वस्थ जीवनशैली और प्रदूषण जैसी आधुनिक चुनौतियों का व्यावहारिक और किफायती समाधान प्रदान करता है।' उन्होंने कहा कि हैदराबाद, पहले से ही नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है और अब उसे योग और समग्र स्वास्थ्य के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में भी उभरना चाहिए।

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में योग समग्र कल्याण के लिए एक वैश्विक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देता है।' स्वास्थ्य और कल्याण पर्यटन में भारत की बढ़ती भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि योग ने समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की पहचान को मजबूत किया है।

उन्होंने हाल ही में शुरू की गई 'योग 365' पहल पर प्रकाश डालते हुए कहा, "योग 365 अभियान के माध्यम से आयुष मंत्रालय, हबील्ड और एमडीएनआईवाई के सहयोग से नागरिकों को योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।" 21 जून तक चलने वाला 100 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण कार्यक्रम एक लाख से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है और इसमें योग मित्र प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने घोषणा की कि आई डी वाई 2026 की उलटी गिनती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला अगला योग महोत्सव मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित किया जाएगा जो भारत की सांस्कृतिक विरासत, वास्तुकला और स्वास्थ्य संबंधी परंपराओं के संगम का प्रतीक है। श्री जाधव ने जापान के ओसाका में आयोजित विश्व एक्सपो 2025 के दौरान छह महीने तक योग सत्र आयोजित करने के लिए हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूशन और योग प्रमाणन बोर्ड के प्रयासों की भी सराहना की।

आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मोनालिसा दास ने हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के योगदान को स्वीकार करते हुए कहा, 'कान्हा शांति वनम योग द्वारा विकसित की जाने वाली शांति और संतुलन को प्रतिबिंबित करता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य और एकता की दिशा में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को प्रज्वलित करना है।'

इस कार्यक्रम में हार्टफुलनेस के अध्यक्ष श्री कमलेश दी पटेल (दाजी), लोकसभा सांसद श्रीमती डीके अरुणा, आयुष मंत्रालय के सचिव पद्म श्री वैद्य राजेश कोटेचा और आयुष मंत्रालय, राज्य प्रशासन तथा प्रमुख योग संस्थानों के अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

योग महोत्सव का एक प्रमुख आकर्षण सामान्य योग प्रणाली (सीवाईपी) का सामूहिक प्रदर्शन था। सत्र का नेतृत्व एमडीएनआईवाई के निदेशक प्रो. (डॉ.) काशीनाथ समागंडी ने एमडीएनआईवाई के योग प्रशिक्षकों के साथ मिलकर किया। सीवाईपी अभ्यास के बाद दाजी द्वारा हार्टफुलनेस मेडिटेशन सत्र का संचालन किया गया। यह आयोजन 21 जून को मनाए जाने वाले अतंर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की राष्ट्रव्यापी तैयारियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कार्यक्रम के अन्य मुख्य आकर्षणों में नाट्ययोग प्रदर्शन और एक कोरियाई टीम द्वारा योगा फ्यूजन प्रस्तुति शामिल थी।

कजाकिस्तान, लेसोथो, बुल्गारिया, क्यूबा, नामीबिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित 20 से अधिक देशों के दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधियों ने इस योग कार्यक्रम में भाग लिया, जो योग के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दशार्ता है।

कान्हा शांति वनम में आयोजित योग महोत्सव, अतंर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो योग के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य, कल्याण और सतत जीवन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

मैजिक नंबर 148 फेल हुआ तो बंगाल में सरकार बनाने का प्लान बी क्या होगा?

एग्जिट पोल के संकेत पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बेहद कांटे की टक्कर की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों ही बहुमत के 148 सीटों के जादुई आंकड़े के आसपास सिमटती नजर आ रही हैं। ऐसे में राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना मजबूत हो गई है, जो आगे चलकर सरकार गठन को जटिल बना सकती है।

इसका अर्थ होगा कि किसी भी दल को अकेले सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं मिलेंगी, जिससे गठबंधन के लिए बातचीत या संभावित राष्ट्रपति शासन की स्थिति बन सकती है। अगर भाजपा और टीएमसी दोनों सरकार बनाने के बहुमत के आंकड़ें नहीं हासिल कर सकें तो सरकार बनाने का प्लान इ क्या होगा? आइए समझते हैं...

दरअसल, पश्चिम बंगाल चुनाव में अधिकांश एग्जिट पोल में जीत का अंतर बेहद सीमित है और मुकाबला बहुमत के आंकड़े के आसपास सिमटा हुआ नजर आ रहा है। सीटों के अनुमान के अनुसार 5-10 सीटों का छोटा सा अंतर भी स्थिर सरकार या त्रिशंकु विधानसभा के बीच फर्क तय कर सकता है। सत्तारूढ़ टीएमसी और राज्य में अपना आधार विस्तार कर रही भाजपा के बीच मुकाबला बेहद कड़ा बना हुआ है।

कांटे की टक्कर, 148 के आसपास अटका जनादेश

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के बाद तमाम पोलिंग एजेंसियों के एग्जिट पोल में भाजपा और टीएमसी के बीच कड़े मुकाबले का अनुमान लगाया गया है।

मैट्रिज (एबीपी) ने भाजपा को 146-161 सीटें और टीएमसी को 125-140 सीटें मिलने का अनुमान लगाया। भाजपा यदि 146 पर रहती है, तो बहुमत से चूक जाएगी।

पीएमआरक्यू ने भाजपा के लिए 150-175 और टीएमसी के लिए 118-138 सीटें बताईं। यहां तक कि 150 का निचला स्तर भी बहुमत (148) से थोड़ा ऊपर है, जो एक नाजुक जनादेश का संकेत है।

त्रिशंकु विधानसभा में सरकार बनाने का प्लान इ क्या होगा?

त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में, राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्यौता देते हैं। यदि भाजपा को बहुमत नहीं मिलता, तो वह छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन ले सकती है। वहीं, टीएमसी, कांग्रेस और वाम दलों की ओर देख सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पार्टी "एक स्पष्ट तस्वीर सामने आने का इंतजार करेगी"।

BJP या TMC बहुमत नहीं साबित कर सकी तो क्या होगा?

सरकार बनने के बाद, उसे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट द्वारा बहुमत साबित करना होगा। यदि कोई गठबंधन सफल नहीं होता, तो अस्थायी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। दुर्लभ परिस्थितियों में, नए सिरे से चुनाव भी संभव हैं। 2026 का बंगाल चुनाव कई मायनों में अनूठा है, पिछली बार के विपरीत यह टीएमसी और भाजपा के बीच सीधा द्विध्रुवीय मुकाबला है।

त्रिशंकु विधानसभा बनी तो BJP या TMC किसके लिए होगी चुनौती?

सत्ता विरोधी वोट विभिन्न राजनीतिक दलों में बंटे हैं, और 92 प्रतिशत से अधिक मतदान मजबूत जन-लामबंदी का संकेत देता है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक यदि त्रिशंकु विधानसभा बनती है, तो भाजपा के लिए चुनौती होगी, भले ही वह सबसे बड़ी पार्टी हो, क्योंकि उसे सहयोगियों पर निर्भरता रहेगी। यह उस राज्य में उसके नियंत्रण को सीमित करेगा जहां पार्टी ममता बनर्जी से सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है।

त्रिशंकु विधानसभा में कौन बनेगा किंगमेकर?

टीएमसी के लिए, यह विपक्षी एकता की परीक्षा हो सकती है। यदि कांग्रेस और वाम दल जैसे उसके राष्ट्रीय सहयोगी उसे समर्थन देते हैं, तो भाजपा से पिछड़ने के बावजूद वह सत्ता में बनी रह सकती है। इससे कांग्रेस और वाम दलों को किंगमेकर की भूमिका निभाने और कम या शून्य सीट हिस्सेदारी के बावजूद अपनी प्रासंगिकता बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

आखिरी नंबर पर चल रही लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए गुड न्यूज, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी टीम से जुड़ा

आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में आखिरी नंबर पर चल रही लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छी खबर है। टीम ने जिस खिलाड़ी को ऑक्शन में 8 करोड़ 60 लाख में खरीदा था। वह टीम से जुड़ गया है।

लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़े जोश इंग्लिस

नई दिल्लीः आईपीएल 2026 में फॉर्म से जूझ रहे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छी खबर है। 4 मई को होने वाले अगले मुकाबले से पहले जोश इंग्लिस टीम से जुड़ गए हैं। वह उस मैच में चयन के लिए उपलब्ध होंगे। इंग्लिस ने नीलामी से पहले ही फ्रेंचाइज़ियों को बता दिया था कि अपनी शादी की वजह से वह आईपीएल 2026 के लिए ज्यादा समय उपलब्ध नहीं रहेंगे। इसके बाद पंजाब किंग्स ने उन्हें रिलीज कर दिया था।

शादी की वजह से इंग्लिस लेट हुए

इसके बाद भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें ऑक्शन में 8.60 करोड़ रुपये में खरीद लिया। उनकी शादी 18 अप्रैल को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मार्गरेट रिवर में हुई। 31 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज इंग्लिस ने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए 11 मैच खेले थे। इसमें उन्होंने 31 की औसत और 162 की स्ट्राइक रेट से 278 रन बनाए थे।

लखनऊ लगातार 5 मैच हार चुकी

जोश इंग्लिस ने लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। 8 मैचों में टीम के सिर्फ 4 ही पॉइंट हैं। पहले तीन मैचों में दो जीत हासिल करने के बाद लखनऊ को अगले 5 मैचों में हार झेलनी पड़ी। टीम के हार की सबसे बड़ी वजह खराब बल्लेबाजी हैं। इंग्लिस के आने से बल्लेबाजी मजबूत होगी। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लिस के नाम दो शतक हैं। वह ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी कर चुके हैं।

मैथ्यू ब्रिट्जके साउथ अफ्रीका गए

वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके वापस अपने देश लौट गए हैं। निजी कारणों से केकेआर के खिलाफ सुपर ओवर में टीम को मिली हार के बाद वह वापस गए। ईएसपीएन की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि ब्रीट्जके इसलिए साउथ अफ्रीका गए हैं क्योंकि हाल ही में उनकी पत्नी के परिवार के किसी करीबी सदस्य का निधन हो गया था। उनके वापस लौटने पर अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उन्हें अभी तक प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला है।

'इतना डर कभी नहीं लगा,' जैमिसन ने बयां की वैभव सूर्यवंशी के खौफ की कहानी, डरते हुए कर रहे थे गेंदबाजी

(जीएनएस)।

दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज काइल जैमिसन ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुए मुकाबले के बाद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्वीकार किया कि मैदान पर पंद्रह साल के इस खिलाड़ी का सामना करना उनके करियर के सबसे दबाव भरे पलों में से एक था। कीवी गेंदबाज ने माना कि इस छोटी उम्र के खिलाड़ी की आक्रामक बल्लेबाजी शैली ने उन्हें काफी चिंतित कर दिया था।

मैच के बाद जैमिसन ने खुलकर अपनी घबराहट के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि एक किशोर खिलाड़ी के खिलाफ गेंदबाजी करते समय वे इतने डरे हुए पहले कभी नहीं रहे थे। वैभव ने इस सीजन में जिस तरह से बड़े-बड़े गेंदबाजों की धुनाई की है और शानदार शतक जड़ा है, उससे विपक्षी खेमे में उनकी बल्लेबाजी को लेकर एक अलग तरह की दहशत पैदा हो गई थी।

मैदान पर तीखी बहस

मुकाबले के दूसरे ही ओवर में जैमिसन ने वैभव को आउट करके

अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई थी। विकेट लेने के बाद उन्होंने युवा बल्लेबाज को काफी आक्रामक अंदाज में विदा किया था। जैमीसन की यह हरकत चर्चा का विषय बन गई क्योंकि उन्होंने वैभव के चेहरे के करीब जाकर कुछ तीखे शब्द कहे थे। इसी व्यवहार के चलते मैच रेफरी ने उन पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया।

अनुशासन का डंडा

मैदान पर दिखाई गई इस आक्रामकता की कीमत जैमीसन को चुकानी पड़ी। बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। नियम के तहत उन्हें एक डिमेरिट अंक दिया गया है और भविष्य के लिए सख्त चेतावनी भी जारी की गई है। अधिकारियों का मानना है कि खेल के दौरान एक अनुभवी खिलाड़ी को युवा खिलाड़ी के प्रति संयम बरतना चाहिए था।

रणनीति का हिस्सा

जैमिसन ने अपनी सफाई में बताया कि दिल्ली कैपिटल्स की योजना राजस्थान की सलामी जोड़ी को जल्दी पवेलियन भेजने की थी। मिचेल स्टार्क के साथ मिलकर उन्होंने पावरप्ले में रनों की गति पर अंकुश लगाने की कोशिश की थी। वैभव का विकेट लेना टीम की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा था क्योंकि वे किसी भी समय मैच को विपक्षी टीम की पकड़ से दूर ले जाने की क्षमता रखते हैं।

भारत में चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन

(जीएनएस)।

भारत आयुष जैसी पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ उन्नत चिकित्सा बुनियादी ढांचे को एकीकृत करके मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। मजबूत नीतिगत समर्थन, डिजिटल सुविधा और आयुष वीजा एवं क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र जैसी पहल इकोसिस्टम को मजबूत कर रही हैं। बढ़ती वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल लागत और समग्र देखभाल की मांग अंतरराष्ट्रीय रोगियों को किफायती, उच्च गुणवत्ता वाले उपचार और निवारक स्वास्थ्य समाधानों के लिए भारत में आने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

भारत एक वैश्विक उपचार गंतव्य के रूप में

दुनिया भर में, स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत, लंबे समय तक प्रतीक्षा समय और जीवन शैली से जुड़े रोगों का बढ़ता बोझ रोगियों को विदेश में इलाज कराने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस वैश्विक बदलाव ने बहु-अरब डॉलर के मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) उद्योग का उदय किया है।

वर्ष 2022 में वैश्विक मेडिकल वैल्यू ट्रैवल बाजार का मूल्य लगभग 115.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके वर्ष 2030 तक लगभग 286.1

बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। बाजार लगभग 10.8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है।

भारत इस विकसित वैश्विक परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक गंतव्य के रूप में उभरा है। उद्योग का अनुमान है कि वर्ष 2025 में चिकित्सा पर्यटन बाजार लगभग 8.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा, जिसमें वर्ष 2030 तक 16.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान है।

सदियों से, भारत को उपचार, संतुलन और रोग मुक्ति की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए एक मुख्य गंतव्य के रूप में माना जाता रहा है। आज, यह प्राचीन विरासत एक गतिशील मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इकोसिस्टम के रूप में विकसित हुई है। यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को पारंपरिक प्रणालियों के कालातीत ज्ञान के साथ जोड़ता है।

प्रमुख "हील इन इंडिया" पहल के माध्यम से, सरकार देश को एकीकृत और समग्र स्वास्थ्य सेवा के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित कर रही है।

इस परिदृश्य के दायरे को समझने के लिए, इसके दो जीवंत स्तंभों के बीच अंतर करना आवश्यक है:

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

लखनऊ पुलिस मुख्यालय में तैनात 34 साल के अरकने की आत्महत्या, परिजनों ने मंगेतर पर लगाए गंभीर आरोप

लखनऊ पुलिस मुख्यालय में तैनात 34 साल के एएसआई सत्येंद्र वर्मा ने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मौके से चार पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ है. सत्येंद्र वर्मा की शादी तय हो चुकी थी. मंगेतर से उनकी बातचीत भी होती थी. परिजनों ने मंगेतर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया है.

(जीएनएस)। राजधानी लखनऊ से चौंकाने वाली घटना सामने आई है. उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में तैनात 34 साल के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (अरक) सत्येंद्र वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उनकी शादी जल्द ही होने वाली थी. उससे पहले ही उन्होंने खौफनाक कदम उठा लिया. परिजनों ने उनकी मंगेतर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इस घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया.

मूल रूप से फतेहपुर जिले के रहने वाले सत्येंद्र वर्मा लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित अहिमामऊ इलाके में किराए पर रहते थे. गुरुवार को उनका शव कमरे में फंदे से लटका मिला. काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर लोगों को शक हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई. कमरे के भीतर सत्येंद्र का शव पंखे से लटका मिला.

तलाशी के दौरान पुलिस को चार पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला. शुरूआती जानकारी के मुताबिक, सुसाइड नोट में सत्येंद्र ने अपनी जिंदगी की असफलताओं के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया है. हालांकि, मृतक के परिजनों ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं.

परिजनों का कहना है कि सत्येंद्र की शादी तय हो चुकी थी और वह अपनी मंगेतर से बातचीत करते थे. परिजनों के अनुसार, आत्महत्या से एक दिन पहले भी सत्येंद्र की अपनी मंगेतर से लंबी बातचीत हुई थी. उनका आरोप है कि इसी बातचीत के बाद वह मानसिक रूप से बेहद परेशान थे.

परिवार का दावा है कि मंगेतर की वजह से ही सत्येंद्र ने यह कदम उठाया. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मंगेतर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. साथ ही, सुसाइड नोट को जांच के लिए रख लिया गया है. पुलिस अब मोबाइल कॉल डिटेल, चैट और अन्य साक्ष्यों की भी जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. सुसाइड नोट, परिजनों के आरोप और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

'बहुत कुछ हार गया हूं, माफ कर देना'; युवा प्रॉपर्टी डीलर का दर्दभरा आखिरी नोट, सट्टेबाजी में हारी जिंदगी

लखनऊ के गुडंबा में प्रॉपर्टी डीलर ने 11वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। आईपीएल सट्टेबाजी में सारी जमा-पूंजी हारने के बाद खौफनाक कदम उठाया।

(जीएनएस)। लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक युवा प्रॉपर्टी डीलर के जिंदगी के अंत की सनसनीखेज घटना सामने आई है। आईपीएल सट्टेबाजी में लिप्त युवक इतना पैसा हार गया कि जिंदगी भी उसके सामने छोटी हो गई। कर्ज के बोझ तले दबे युवक ने आखिरकार अपनी बिल्डिंग की 11वीं मंजिल से छलांग लगाकर जिंदगी का अंत कर दिया। पुलिस ने जब उसके कमरे की तलाशी ली तो वहां सुसाइड नोट मिला है। इस आखिरी नोट में युवक का दर्द सामने आया। बिल्डिंग से छलांग लगाने से पहले वह पत्नी को कॉल कर खूब रोया। उससे माफी मांगी। इसके बाद खौफनाक कदम उठा लिया।

सुसाइड नोट में क्या है?

लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र स्थित जनेश्वर अपार्टमेंट में 35 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर प्रबल जैन की 11वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या का मामला सामने आया है। वह वहां अपनी पत्नी के साथ वहां किराए पर रहते थे। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें उसने आईपीएल सट्टेबाजी में अपनी पूरी जमा-पूंजी हारने का जिक्र किया है। अपनी पत्नी एवं परिवार से माफी मांगी है। प्रबल ने सुसाइड नोट में लिखा कि वह आईपीएल सट्टे में लाखों रुपये हार गया है। कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। इस स्थिति में जीना उसे दूभर लग रहा है।

मौके पर पहुंची पुलिस

युवक की कूदकर मौत की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर गुडंबा अंजनी कुमार मिश्रा फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तलाशी के दौरान फ्लैट ऊ-1102 से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया। पुलिस ने दो मोबाइल फोन और सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक मूल रूप से सीतापुर के महमूदाबाद का निवासी था। गुरुवार रात करीब 8:45 बजे जब सोसाइटी के लोग नीचे टहल रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान प्रबल ने 11वीं मंजिल से छलांग लगा दी।

पत्नी को कॉल कर रोया

प्रबल ने 11वीं मंजिल से छलांग लगाने से पहले पत्नी शिवानी को फोन किया। कॉल पर वह फूट-फूटकर रोया। आत्महत्या करने की बात कही। पत्नी उसे समझाने और शांत करने की कोशिश करती रही। प्रबल ने फोन काट दिया। शिवानी जब तक मौके पर पहुंची, तब तक प्रबल खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था। पत्नी शिवानी ने पुलिस को बताया कि प्रबल लगातार आईपीएल मैच देख रहे थे। घटना से ठीक पहले उन्होंने फोन पर रोते हुए कहा था कि वह बहुत कुछ हार गए हैं, जिसके बाद फोन कट गया।

कुर्सी रोड में रहने वाले प्रबल जैन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रबल के बैंक स्टेटमेंट और परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। - अनिंद्य विक्रम सिंह, एसीपी गाजीपुर

दोनों ने की थी लव मैरिज

प्रबल और शिवानी ने लव मैरिज की थी। प्रबल ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। वहीं झारखंड के बोकारो की रहने वाली शिवानी भी पढ़ती थी। पढ़ाई के दौरान दोनों में प्यार हो गया। डेढ़ साल पहले ही उन्होंने शादी की थी। शिवानी लखनऊ के एक मॉल में ग्राउंड फ्लोर मैनेजर के पद पर काम करती है। दोनों पिछले साल दिवाली के समय जनेश्वर इन्क्लेव में किराए पर रहने आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रबल के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है। उसके पिता ने भी कुछ समय पहले आत्महत्या की थी।

लखनऊ को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत! बनेगा 108 करोड़ में नया फ्लाईओवर, इन जिलों को भी होगा लाभ

(जीएनएस)। लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए 108 करोड़ रुपये की लागत से एक नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा. यह परियोजना लंबे समय से प्रस्तावित थी और अब इसे मंजूरी मिलने के बाद मई 2026 से इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे शहर के यातायात प्रबंधन में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है.

कितनी होगा फ्लाईओवर की लंबाई?

इस फ्लाईओवर की लंबाई करीब 960 मीटर होगी और इसे तैयार करने में लगभग डेढ़ से पौने दो साल का समय लगेगा. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की एनएच शाखा द्वारा कराया जाएगा, जिसने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं.

परियोजना के लिए मशीनें और संसाधन भी जुटाए जा चुके हैं.

फ्लाईओवर के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा

फ्लाईओवर के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बना फुटओवर ब्रिज था, जिसे अब हटाने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा बिजली और जलकल विभाग की लाइनों को भी शिफ्ट किया जाएगा ताकि निर्माण के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या या जनता को असुविधा न हो. इस परियोजना के पीछे क्षेत्रीय विधायक डॉ. नीरज बोरा के लगातार प्रयास रहे हैं. साथ ही राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के समक्ष इस प्रस्ताव को उठाया गया था, जिसके बाद इसे प्राथमिकता मिली और अब यह योजना जमीन पर उतरने जा रही है.

इन जिलों को भी होगा लाभ

फ्लाईओवर बनने से अयोध्या रोड और सीतापुर रोड के बीच यात्रा काफी आसान और तेज हो जाएगी. यह मार्ग आईआईएम रोड, मडियांव, टेढ़ी पुलिया, खुर्रमनगर, मुंशी पुलिया और पॉलिटेक्निक जैसे प्रमुख फ्लाईओवरों से जुड़कर एक बेहतर ट्रैफिक कॉरिडोर बनाएगा, जिससे शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा.

नौसेना प्रमुख की 2 से 5 मई 2026 तक म्यांमार की यात्रा

नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 2 से 5 मई 2026 तक म्यांमार की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं।

नई दिल्ली, (जीएनएस)। इस यात्रा के दौरान, नौसेना प्रमुख म्यांमार सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ जनरल ये विन ऊ, म्यांमार के रक्षा मंत्री जनरल यू हटुन आंग और म्यांमार नौसेना के कमांडर-इन-चीफ एडमिरल हेटिन विन के साथ-साथ म्यांमार सशस्त्र बलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इन वाताओं से चल रहे द्विपक्षीय समुद्री सहयोग की समीक्षा करने, परिचालन स्तर पर संबंधों को मजबूत करने और दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का अवसर मिलेगा।

इस यात्रा में म्यांमार नौसेना के केंद्रीय नौसेना कमान, नौसेना प्रशिक्षण कमान और प्रथम बेड़े में कार्यक्रम और म्यांमार सशस्त्र बलों के शहीद नायकों के युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करना शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में रक्षा सहयोग से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी, जिनमें समुद्री सुरक्षा, क्षमता विकास, क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भारतीय नौसेना रक्षा सहयोग बैठकों, स्टाफ वाताओं, प्रशिक्षण आदान-प्रदान और भारत-म्यांमार नौसेना अभ्यास (आईएमएनईएक्स), भारत-म्यांमार समन्वित गश्त (आईएमसीओआर), बंदरगाह के दौरों और जल सर्वेक्षणों सहित परिचालन संबंधी गतिविधियों के माध्यम से म्यांमार नौसेना के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहती है। इसके अतिरिक्त, दोनों नौसेनाएं नियमित रूप से प्रशिक्षण आदान-प्रदान को आगे बढ़ाती हैं, बहुपक्षीय मंचों में भाग लेती हैं और क्षमता विकास की दिशा में सहयोग करती हैं। म्यांमार ने भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित हालिया सभी कार्यक्रमों में भाग लिया है, जैसे कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, मिलन, अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा, गोवा समुद्री सम्मेलन/संगोष्ठी, आईओएस सागर और एडमिरल कप।

नौसेना प्रमुख की यह यात्रा भारत-म्यांमार के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों की पुष्टि करती है। यह मित्रता आपसी सम्मान, विश्वास और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और स्थिरता के लिए साझा प्रतिबद्धता पर आधारित

मई की भीषण गर्मी को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं; सरल सावधानियों से इसके प्रभाव को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है: डॉ. जितेंद्र सिंह

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जनता से लू की भविष्यवाणी पर अनावश्यक प्रतिक्रिया न देने का आग्रह किया

सरकार ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूवार्नुमान के आधार पर सलाह जारी की; जागरूकता, तैयारी और जिम्मेदार प्रतिक्रिया का आ 'ान किया

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने किसानों को लू की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यों की योजना बनाने की सलाह दी; वर्तमान परिस्थितियाँ आम तौर पर रबी की फसल की देर से कटाई के लिए अनुकूल हैं

(जीएनएस)। केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्‍ य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज आम जनता को आश्वस्त किया कि मई महीने के दौरान अनुमानित या अपेक्षित गर्मी की स्थिति को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है और मौसम पूवार्नुमान को सही ढंग से समझकर और दिन-प्रतिदिन की सरल सावधानियों का पालन करके किसी भी अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचा जा सकता है।

अपने कार्यालय में मीडिया को जानकारी देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यद्यपि कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक तापमान और लू की स्थिति देखी जा सकती है लेकिन यह स्थिति पूरे देश में एक समान नहीं है और समय पर तैयारी और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली सलाहों का पालन करके इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

आईएमडी द्वारा जारी नवीनतम मासिक पूवार्नुमान और आगे की अवधि के पूवार्नुमान का उल्‍ लेख करते हुए मंत्री जी ने कहा कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर-पूर्वी और

उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है जबकि देश के बड़े हिस्से में इस महीने तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है। कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।

उन्होंने आगे कहा कि पूवार्नुमान के अनुसार हिमालय की तलहटी, ओडिशा सहित पूर्वी तट के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे तमिलनाडु, साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र में लू चलने की संभावना है, जिससे इन क्षेत्रों में सामान्य से लगभग 2-4 दिन अधिक लू चलने की आशंका है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बढ़े पूवार्नुमान के अनुसार बताया कि मई के दूसरे (8-14 मई) और चौथे (22-28 मई) सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहने की संभावना है, जिससे उत्तर-पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों के साथ-साथ पूर्वी तट में लू चल सकती है। पहले और तीसरे सप्ताह (1-7 मई और 15-21 मई) के दौरान, पश्चिमी विक्षोभ और गरज के साथ होने वाली बारिश और बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है।

मंत्री जी ने कहा कि कुछ समय के दौरान रात के तापमान में वृद्धि से उमस बढ़ सकती है, खासकर शहरी और तटीय क्षेत्रों में। पूर्वी तट, गुजरात और महाराष्ट्र में भी गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है।

उन्होंने वैश्विक जलवायु परिस्थितियों पर कहा कि वर्तमान में ईएनएसओ-तटस्थ स्थितियां बनी हुई हैं और दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान अल नीनो की स्थिति होने की संभावना है।

मंत्री जी ने कहा कि सरकार गर्मी से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और उन्होंने पेयजल की उपलब्धता, सुचारू शीतलन व्यवस्था और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। शिशुओं, बुजुर्गों और बाहरी कार्यों में लगे श्रमिकों सहित संवेदनशील समूहों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मंत्री जी ने कृषि के संबंध में कहा कि उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में रबी की फसल की देर से कटाई के लिए परिस्थितियाँ आम तौर पर अनुकूल हैं। हालांकि, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी से चावल (बोरो), मक्का और दालों जैसी कुछ ग्रीष्मकालीन फसलों पर असर पड़ सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे खेतों में सुबह और शाम के समय काम करें, पर्याप्त और नियमित सिंचाई सुनिश्चित करें और अपने पशुओं की सुरक्षा के उपाय करें।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक स्पष्ट जन सलाह जारी करते हुए नागरिकों से पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, भीषण गर्मी के दौरान लंबे समय तक धूप में रहने से बचने और अपने आसपास के संवेदनशील व्यक्तियों की जरूरतों का ध्यान रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आईएमडी के दैनिक अपडेट और प्रभाव-आधारित पूवार्नुमानों का पालन करने से संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी।

मंत्री जी ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की पूवार्नुमान क्षमताओं में काफी सुधार हुआ है जिससे अलर्ट का अधिक सटीक और समय पर प्रसार संभव हो पाया है। यह प्रभावी प्रतिक्रिया और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

मौसम संबंधी अद्यतन जानकारी आईएमडी की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन जैसे कि मौसम ऐप, मौसमग्राम पोर्टल और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से उपलब्ध है।

फोटोः केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह शनिवार को नई दिल्ली में मई 2026 के दौरान संभावित भीषण गर्मी की स्थिति के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए।

यूपी ने राजस्व मामलों के निस्तारण में बनाया रिकॉर्ड, अप्रैल में सुलझाए गए 3.37 लाख से ज्यादा केस; लखनऊ और जौनपुर ने गाड़े झंडे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त निगरानी में उत्तर प्रदेश ने अप्रैल में 3.37 लाख से अधिक राजस्व मामलों का निस्तारण कर रिकॉर्ड बनाया है। राजधानी लखनऊ ...और

(जीएनएस)। लखनऊ। प्रदेश में राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त मॉनीटरिंग का असर साफ नजर आ रहा है। सीएम योगी हर माह जिलावार मामलों की समीक्षा भी करते हैं। योगी सरकार की विशेष पहल के तहत तेजी से मामलों के निपटारे की रणनीति को अपनाया गया, जिससे राजस्व विवादों के मामलों में बड़ा सुधार देखने को मिला है। इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश भर में राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी देखी गयी है। राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) की अप्रैल माह की जारी रिपोर्ट में पूरे प्रदेश में सबसे अधिक राजधानी लखनऊ में मामलों को निस्तारित किया गया है जबकि जनपद स्तरीय न्यायालय में राजस्व के मामले निपटाने में एक बार फिर जौनपुर ने बाजी मारी है। जनपद स्तरीय न्यायालयों में राजस्व वादों के निस्तारण में पिछले 16 माह से जौनपुर टॉप फाइव जिलों में बना हुआ है।

लखनऊ में सबसे अधिक कुल 18,861 मामले निस्तारित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि राजस्व विवादों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर

सुलझाया जाए। उनकी इस पहल का उद्देश्य न केवल जनता को त्वरित न्याय दिलाना है, बल्कि प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देना है। इसी के तहत सभी जिलाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी पूरी तत्परता से मामलों का निस्तारण कर रहे हैं। राजस्व परिषद की आरसीसीएमएस की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में पूरे प्रदेश में कुल 3,37,708 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया। लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने बताया कि सबसे अधिक राजधानी लखनऊ में 18,861 मामले निस्तारित किए गए, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक हैं। इसके बाद प्रयागराज कुल 12,036 मामलों को निस्तारित कर पूरे प्रदेश में दूसरे, बाराबंकी 9,139 मामलों को निस्तारित कर तीसरे स्थान पर है।

आजमगढ़ ने 8,483 मामले निस्तारित कर प्रदेश में चौथा स्थान किया प्राप्त

आजमगढ़ ने 8,483 मामले निस्तारित कर प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। आजमगढ़ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप राजस्व मामलों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जनशिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रहीं हैं। राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर निपटाया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि आजमगढ़ ने अप्रैल में राजस्व मामलों के निस्तारण में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह बरेली ने 8,483 मामले निस्तारित कर पांचवां और जौनपुर ने 8,274 मामलों का निस्तारण कर छठवां स्थान प्राप्त किया है।

जनपद स्तरीय न्यायालयों में जौनपुर ने मारी बाजी, 535 मामले किए निस्तारित

जौनपुर डीएम डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार राजस्व मामलों को निस्तारित किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ रेवन्यू की अप्रैल माह की राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) की रिपोर्ट के अनुसार जौनपुर की पांच राजस्व न्यायालयों ने बोर्ड के निर्धारित मानक के निस्तारण से अधिक मामलों का निस्तारण किया है।

जौनपुर की पांच राजस्व न्यायालयों ने बोर्ड के प्रति माह निस्तारण के मानक 250 के सापेक्ष 535 मामलों का निस्तारण किया है। इसका अनुपात 214.00 प्रतिशत है। इसी के साथ जनपदीय न्यायालय में राजस्व मामलों के निस्तारण में प्रदेश में जौनपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है जबकि मानक 350 के सापेक्ष 370 मामलों का निस्तारण कर दूसरे स्थान पर सुल्तानपुर और मानक 190 के सापेक्ष 199 मामले निस्तारित कर तीसरे स्थान पर गाजीपुर है।

सीएम योगी का सख्त आदेश- तुरंत एक्शन लें अधिकारी, आम आदमी को दिक्कत हुई तो नपेंगे अफसर

सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन से जुड़े अफसरों को सख्त दिशा-निर्देश दिए हैं। CM ने कहा है कि अफसर मौके पर जाकर जल जीवन मिशन से जुड़ी शिकायतों और प्रगति कार्यों का निरीक्षण करें। इसके साथ ही CM योगी ने लापरवाह अफसरों को सख्त चेतावनी दी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत सड़कों की खुदाई के बाद सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने और कार्य पूरा होते ही गड्ढों व खोदी गई सड़कों को तत्काल भरने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने लापरवाह अफसरों को सख्त चेतावनी दी है। सीएम योगी ने लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और कार्यदायी संस्थाओं पर जुमार्ना लगाने के साथ उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी भी दी है।

CM योगी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के कार्यों के दौरान जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। खुदाई के समय सभी सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। काम पूरा होते ही सड़क व गड्ढे भर दिए जाएं, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार शहरी इलाकों से लेकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक साफ-सुथरा पेयजल पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रदेश के करोड़ों लोगों को नल से जल आपूर्ति का लाभ मिल रहा है।

मौके पर जाकर निरीक्षण करें अधिकारी, लापरवाही हुई तो होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। उट के निदेर्शानुसार, अब प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी, जल जीवन मिशन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी तथा संबंधित विभागीय अधिकारी नियमित स्थलीय निरीक्षण करेंगे। वे खुदाई की स्थिति का जायजा लेंगे और खोदी गई सड़कों-गड्ढों को तुरंत भरने की प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जल समाधान पोर्टल पर दर्ज आपूर्ति, लीकेज और खुदाई से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

लापरवाही करने वाली एजेंसियों एवं ठेकेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई

उट योगी ने साफ कहा कि काम को समय पर पूरा न करने, अधूरा छोड़ने या लापरवाही करने वाली एजेंसियों व ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में केवल जुमार्ना वसूला जाएगा बल्कि दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा।

अजय राय का मेदांता अस्पताल से आया हेल्थ बुलेटिन, स्थिति में हो रहा है सुधार; यूपी कांग्रेस ने दी जानकारी

अजय राय की तबीयत में अब तेजी से सुधार हो रहा है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में बेहोश होने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। अब उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है।

लखनऊः (जीएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की तबीयत में सुधार हुआ है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। शुक्रवार शाम को उन्हें मेदांता अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में बेहोशी की अवस्था में भर्ती कराया गया था। जांच में उनके शरीर में सोडियम का स्तर कम पाया गया था। डॉक्टरों के अनुसार, उपचार के दौरान सोडियम स्तर को नियंत्रित कर स्थिर किया गया है। फिलहाल उनकी हालत में सुधार है उन्हें कभी डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।

यूपी कांग्रेस ने दी जानकारी

लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की हेल्थ बुलेटिन जारी की गई है। इसके बारे में यूपी कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष मनीष हिंदवी की ओर से जानकारी दी गई है। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक, 56 वर्षीय यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को शुक्रवार की शाम लगभग 6:30 बजे इमरजेंसी विभाग में लाय गया। उस समय वे अचेत अवस्था में थे। उन्हें दौरे की शिकायत हुई थी।

हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, प्रारंभिक जांच में अजय राय के ब्लड में सोडियम का स्तर कम पाया गया। अस्पताल के अनुसार, अभी उनका उपचार क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉ. दिलीप एवं उनकी टीम की निगरानी में चल रहा है। उपचार के दौरान उनके सोडियम स्तर को नियंत्रित एवं स्थिर किया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति में सुधार है। उन्हें आईसीयू में डॉक्टरों की सतत निगरानी में रखा गया है।

पीएम मोदी ने भी जताई चिंता

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण समर्थकों में उनके स्वास्थ्य को चिंता व्याप्त हो गई थी। वहीं, वाराणसी लोकसभा सीट पर उनके खिलाफ उम्मीदवार रहे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उनके पोस्ट पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिक्रिया जताई।

लखनऊ में 10 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा एक और अंडरपास, पीएम टेक्सटाइल पार्क को करेगा कनेक्ट

(जीएनएस)।

लखनऊ। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पीएम टेक्सटाइल तक जाने वाले मार्ग, सेतु से जुड़े सभी काम को कराने के निर्देश शासन ने कार्यदायी संस्था को दिए थे। इसमें सेतु निगम ने तो गोमती नदी के ऊपर सेतु बनाने का काम समय से पूरा कर लिया। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) आउटर रिंग रोड के नीचे से दो लेन के अंडरपास को चार लेन करने का काम भी कर रहा है।

इस काम को पंद्रह जुलाई 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। दस करोड़ की लागत से बनाए जा रहे अंडरपास को, जो 18 मीटर है, उसे बढ़ाकर 36 मीटर किया जा रहा है। फोर लेन से भी अधिक यह चौड़ा होगा। भविष्य की योजनाओं को देखते हुए प्राधिकरण इसे बनवा रहा है। खासबात है कि दिसंबर 2026 तक प्रोजेक्ट पूरा करवाने के लिए शासन लगा हुआ है, इस अंडरपास से जुड़े काम को जल्द करवाने के लिए एनएचएआइ को भी दस करोड़ की धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है।

आईआईएम रोड से पीएम टेक्सटाइल तक करीब 14.28 किमी. सड़क बनाई जानी है। इसमें छह किमी. की सड़क का चौड़ीकरण लोक निर्माण विभाग करवा चुका है। बाकी आठ किमी. की सड़क का काम अभी तक नहीं शुरू हो पाया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जमीन अधिगृहण का काम चल रहा है। खातेदार ज्यादा होने के कारण शासन यहां भी मुआवजे की प्रकिया पूरी नहीं करवा पाया है। वहीं दिसंबर तक फोर लेन सड़क लोक निर्माण विभाग को बनाकर देना है। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले पीएम टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन करने की तैयारी है।

सेतु निगम ने 212 मीटर के दो पुलों को निर्धारित समय से पहले बनाकर किया तैयार

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने पीएम टेक्सटाइल पार्क को कनेक्ट करने वाले पुल से जुड़ा काम निर्धारित अवधि से तीन से चार माह पहले ही खत्म कर लिया था। गोमती नदी के ऊपर से यह सेतु पीएम टेक्सटाइल पार्क को जोड़ने के लिए बनाया गया है। इस सेतु के बनने से सबसे अधिक लाभ एक दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को होगा।

खास बात है कि एक सेतु से लोग चढ़ सकेंगे और दूसरे सेतु से उतर सकेंगे। अगल-बगल बने प्रत्येक सेतु की लंबाई 212 मीटर रखी गई है। इन सेतु के बन जाने से मलिहाबाद के अटारी गांव में बन रहे प्रधानमंत्री टेक्सटाइल पार्क तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। वर्तमान में लोगों को अटारी तक पहुंचने के लिए जेहटा गांव का रास्ता अपनाना पड़ता है।

पुल से नौ किमी. दूरी पर है पीएम टेक्सटाइल पार्क

रैथा सेतु से पीएम टेक्सटाइल पार्क मात्र नौ किमी. की दूरी पर है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम इस प्रोजेक्ट पर करीब 44.11 करोड़ खर्च करके इसे बनाया है। सेतु निगम के अभियंता बताते हैं कि पीएम टेक्स्टाइल पार्क बनने की घोषणा होने के चंद सप्ताह में ही इस सेतु का खाका तैयार कर लिया गया था। यह सेतु रैथा गांव से उठेगा और कोलवा गांव में उतरेगा।

मतगणना से पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती पर दखल से इनकार

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए 4 मई को होने वाली ऐतिहासिक मतगणना से ठीक दो दिन पहले, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है।

कोर्ट ने मतगणना केंद्रों पर केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ दायर टीएमसी की याचिका पर कोई भी नया दिशा-निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की विशेष पीठ ने शनिवार, 2 मई को हुई इस महत्वपूर्ण सुनवाई में स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग (ECI) अपने द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार मतगणना प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।

अदालत ने क्यों कहा-नियमों के खिलाफ नहीं है नियुक्ति?

टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें प्रत्येक काउंटिंग टेबल पर कम से कम एक केंद्रीय कर्मचारी (सुपरवाइजर या सहायक) की अनिवार्य उपस्थिति के चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराया गया था।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की बेंच ने कहा कि प्रावधानों के अनुसार, मतगणना सुपरवाइजर और सहायकों की नियुक्ति राज्य या केंद्र किसी भी पूल से की जा सकती है। इसे नियमों के खिलाफ नहीं माना जा सकता। अदालत ने चुनाव आयोग के उस बयान को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें आयोग ने भरोसा दिलाया है कि 13 अप्रैल के सर्कुलर को उसकी मूल भावना के साथ लागू किया जाएगा, यानी अधिकारियों की नियुक्ति में संतुलन और पारदर्शिता बरती जाएगी।

सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तीखी दलीलें पेश कीं। उन्होंने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें वहां से न्याय की उम्मीद नहीं है। सिब्बल ने मुख्य रूप से चार आपत्तियां दर्ज कराईं। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग गुपचुप तरीके से बैठकें कर रहा है और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा नहीं की जा रही हैं।

अतिरिक्त पर्यवेक्षक की जरूरत क्यों?

सिब्बल ने तर्क दिया कि जब हर टेबल पर पहले से ही केंद्र का एक 'माइक्रो ऑब्जर्वर' मौजूद है, तो एक और केंद्रीय कर्मचारी को सुपरवाइजर के तौर पर लगाने की क्या आवश्यकता है? टीएमसी का दावा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी उस दल (भाजपा) के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं जो राज्य में उनकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी है, जिससे निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

TMC ने बदला रुख, पर नहीं मिली राहत

सुनवाई के आखिरी चरण में टीएमसी ने अपना रुख थोड़ा नरम किया। सिब्बल ने अनुरोध किया कि अगर केंद्रीय कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं, तो कम से कम हर टेबल पर एक व्यक्ति राज्य सरकार का कर्मचारी भी होना चाहिए। हालांकि, अदालत ने इस पर कोई विशेष निर्देश देने के बजाय चुनाव आयोग के विवेक पर ही भरोसा जताया। बेंच ने सिब्बल की दलीलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "स्थिति वैसी नहीं है जैसा आप बता रहे हैं," और याचिका का निपटारा कर दिया।

अब 4 मई की मतगणना पर सबकी नजर

कलकत्ता हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद, ममता बनर्जी की पार्टी को अब चुनाव आयोग की वर्तमान व्यवस्था के तहत ही मतगणना में शामिल होना होगा। राज्य भर में 700 कंपनियां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनात हैं और सभी 291 सीटों (3 सीटों पर सहयोगियों के साथ) के लिए सुरक्षा के 'थ्री-लेयर' इंतजाम किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए अतिरिक्त पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों को तैनात किया

(जीएनएस)।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2026 के आम चुनाव के लिए मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा को मजबूत करने और कानून एवं व्यवस्था की निगरानी और मतगणना पर्यवेक्षकों की सहायता के लिए 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों एवं 77 पुलिस पर्यवेक्षकों को तैनात किया है।

अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है कि मतगणना की कार्यवाही सुरक्षित, शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शी वातावरण में संचालित हो।

ये नियुक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी के तहत आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई हैं। इस अवधि के दौरान पर्यवेक्षकों को आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और वे आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करेंगे।

165 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जहां एक से अधिक मतगणना कक्ष हैं वहां मतगणना पर्यवेक्षकों की सहायता के लिए अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है।

पुलिस पर्यवेक्षक अपने-अपने निर्धारित मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा और कानून व्यवस्था की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था आयोग के निदेर्शों के अनुसार हो। हालांकि मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे।

पुलिस पर्यवेक्षक मतगणना पर्यवेक्षकों और मतगणना प्रक्रिया के लिए तैनात अन्य चुनावी तंत्र के साथ मिलकर कार्य करेंगे।

रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ), मतगणना कर्मियों, उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के लिए पहचान पत्र रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) द्वारा ईसीआईएनईटी में एक समर्पित मॉड्यूल के माध्यम से जारी किए जाएंगे ।

मतगणना कर्मियों, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के लिए आरओ द्वारा ईसीआईएनईटी के माध्यम से जारी किए गए क्यूआर कोड आधारित फोटो आईडी पर ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश होगा।

एकेटीयू लखनऊ में गुजरात राज्य स्थापना दिवस पर हुआ आयोजन

डा. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) में शुक्रवार को गुजरात की संस्कृति, परंपरा और विरासत जीवंत हो गई। मौका था वीसी प्रो. जेपी पांडेय के निर्देशन में आयोजित गुजरात राज्य स्थापना दिवस के भव्य कार्यक्रम का। कार्यक्रम का शुभारंभ गुजराती संस्कृति पर आधारित नृत्य प्रस्तुति की।

लखनऊ (जीएनएस)। । डा। एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) में शुक्रवार को गुजरात की संस्कृति, परंपरा और विरासत जीवंत हो गई। मौका था वीसी प्रो। जेपी पांडेय के निर्देशन में आयोजित गुजरात राज्य स्थापना दिवस के भव्य कार्यक्रम का। कार्यक्रम का शुभारंभ गुजराती संस्कृति पर आधारित नृत्य प्रस्तुति की। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अपने मनमोहक अंदाज में गुजराती नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। पारंपरिक गुजराती वेश-भूषा में स्टूडेंट्स ने फैशन शो में अपनी कला प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया। गुजरात राज्य के गठन को लेकर 1956 में हुए आंदोलन की घटना पर आधारित लघु नाटिका की संजीदा प्रस्तुति भी दी गई। छात्राओं ने गुजरात के व्यापारिक सोच का संदेश देता नाटक भी मंच पर साकार किया। उन्होंने गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य प्रस्तुत किया तो हाल तालियों से गूंज उठा।

आयोजन के दौरान वीसी प्रो। जेपी पांडेय ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से समुद्र के किनारे वाले राज्य समृद्ध ही रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण व्यापारिक रास्ते का होना है। साथ ही ऐसे प्रदेश व्यापार केंद्रित होते हैं। साथ ही सांस्कृतिक रूप से भी ये राज्य काफी विपुल होते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स का इन राज्यों की संस्कृति को जानना काफी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में कार्यवाहक कुलसचिव केशव सिंह, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो। ओपी सिंह, परीक्षा नियंत्रक प्रो। दीपक नगरिया भी मौजूद रहे।

वहीं, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में गुजरात स्थापना दिवस के अवसर पर कैंपस में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें स्टूडेंट्स ने गुजरात की समृद्ध लोकसंस्कृति, परंपराओं एवं कला पर आधारित बेहतरीन प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में डा। काजिम रिजवी और मोहसिन हैदर की से तैयार की गई 10 मिनट की डाक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें गुजरात की सांस्कृतिक विरासत, राजनीतिक पृष्ठभूमि एवं ऐतिहासिक महत्व को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया।

गुजरात स्थापना दिवस पर अटल सभागार में गुजरात की संस्कृति और स्वाद का अनूठा संगम देखने को मिला। गृह विज्ञान विभाग के विद्यार्थियों ने अपनी पाक कला का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न प्रसिद्ध गुजराती व्यंजनों के स्टाल लगाए। वीसी प्रो। अजय तनेजा ने इन व्यंजनों का स्वाद भी चखा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल विद्यार्थियों को विभिन्न राज्यों की संस्कृति से परिचित कराते हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी मजबूत करते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में लखनऊ की बास्केट चाट का जलवा, पीएम मोदी भी कर चुके 'लखनवी चाट के राजा' की प्रशंसा

(जीएनएस)।

लखनऊ। लखनवी खानपान की दुनिया दीवानी है। यह शहर न केवल खाने की विरासत को संजोए हुए है, बल्कि अपने भोजन में समाज के हर वर्ग के लोगों का स्वाद भी समाहित किए हुए है।

इनमें से एक लखनवी बास्केट चाट का जायका अलग ही है। हजरतगंज, चौक, चटोरी गली और अन्य स्थानों पर दिनभर चाट खाने वाले आते रहते हैं। बास्केट चाट है ही ऐसी कि एक बार खाइए, बार-बार खाने को जी चाहेगा।

हाल ही में लखनऊ की बास्केट चाट ऑस्ट्रेलिया में खूब पसंद की गई है। इस स्ट्रीट फूड बास्केट चाट ने मास्टरशेफ ऑस्ट्रेलिया-2026 की शीर्ष 10 प्रविष्टियों में जगह बनाई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी लखनऊ के चाट की प्रशंसा 2023 में ऑस्ट्रेलिया में ही कर चुके हैं। पिछले वर्ष नवंबर में यूनेस्को द्वारा 'क्रिएटिव सिटी आफ गैस्ट्रोनामी' से सम्मानित लखनऊ के व्यंजनों की पहचान दुनियाभर में है।

भारतीय मूल की प्रतिभागी कनिका गद्योक ने 19 अप्रैल से शुरू मास्टरशेफ ऑस्ट्रेलिया-2026 में 'कटोरीचाट' (बास्केट चाट) को प्रस्तुत किया। इस व्यंजन ने बटरफ्लाई ट्राउट, आक्स-टेल रैवियोली और बटेर सहित कई व्यंजनों को पीछे छोड़ दिया।

कुरकुरे पैटी, चटपटी चटनी के स्वादों से भरपूर यह व्यंजन आलू के टुकड़ों और आटे से बनी खाने वाली टोकरी में परोसा जाता है, जिसमें स्वादिष्ट सामग्री भल्ले, पापड़ी, उबली मटर, दही, मसाले, सेव, अनार दाना आदि का मिश्रण भरा होता है। इसे 'लखनवी चाट का राजा' कहा जाता है।

तीन दशक पहले हुआ बास्केट चाट का जन्म

इस मशहूर चाट की कहानी किसी सोची-समझी रेसिपी का परिणाम नहीं, बल्कि एक दिलचस्प संयोग है। करीब तीन दशक पहले लखनऊ के शेफ हरदयाल मौर्य आलू के लच्छों से कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे थे।

गरम कड़ाही पर आलू के लच्छे चिपक गए और जब उसे तेल में डाला तो वो एक 'टोकरी' के आकार में आ गए। यहीं से जन्म हुआ लखनऊ की 'बास्केट चाट' का। शहर में कोई भी विशिष्ट व्यक्ति आता है तो यहां की चाट का लुत्फ अवश्य लेता है।

प्रधानमंत्री ने सिडनी में सराहा था

मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लखनऊ की चाट की प्रशंसा की थी। उन्होंने यहां के खान-पान का जिक्र करते हुए कहा था- जब खाने की बात चलती है तो चाट की बात आती है और लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है।

क्रिएटिव सिटी आफ गैस्ट्रोनामी से बढ़ी प्रसिद्धि

यूनेस्को ने गत वर्ष 31 अक्टूबर को लखनऊ को अपनी 'क्रिएटिव सिटी आफ गैस्ट्रोनामी' की श्रेणी में शामिल किया था। यह लखनऊ के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, जो इसे दुनिया के बेहतरीन खान-पान वाले शहरों के साथ खड़ा करता है। इस सम्मान से लखनऊ के व्यंजनों की प्रसिद्धि दुनियाभर में बढ़ रही है।

8 बड़े मंगल से लखनऊ में भक्ति का सैलाब, मंदिरों में तैयारी तेज, भंडारों की धूम

ज्येष्ठ मास की शुरूआत के साथ लखनऊ में भक्ति का माहौल गहरा गया है। इस बार 8 बड़े मंगल पड़ने से मंदिरों, भंडारों और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है।

मंदिरों की सफाई से लेकर भंडारों की तैयारियां पूरी, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन सतर्क

(जीएनएस)।

धार्मिक आस्था और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध राजधानी लखनऊ में ज्येष्ठ मास की शुरूआत के साथ ही भक्ति का माहौल चरम पर पहुंच गया है। इस बार ज्येष्ठ मास खास होने जा रहा है, क्योंकि अधिक मास के कारण पूरे दो महीनों तक चलने वाले इस पावन काल में कुल 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। इसे लेकर शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में तैयारियां जोरों पर हैं और प्रशासन भी श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम कर रहा है।

मंदिरों में सफाई और सजावट का दौर

ज्येष्ठ मास के आरंभ के साथ ही शहर के सभी प्रमुख हनुमान मंदिरों में साफ-सफाई और सजावट का कार्य तेज कर दिया गया है। मंदिर परिसर को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। फूलों, रोशनी और धार्मिक सजावट से मंदिरों को भव्य रूप दिया जा रहा है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को एक दिव्य वातावरण का अनुभव हो। हर साल की तरह इस बार भी बड़े मंगल पर लाखों की संख्या में भक्त हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंधन समितियां पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई हैं।

भक्तों की भीड़ को लेकर विशेष प्रबंध

ज्येष्ठ मास में विशेषकर मंगलवार के दिन, जिन्हें 'बड़ा मंगल' कहा जाता है, हनुमान मंदिरों में लंबी-लंबी कतारें लगती हैं। इस बार 8 बड़े मंगल होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी की संभावना है। भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग, कतार प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन मिलकर ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने की योजना पर काम कर रहे हैं, ताकि शहर में जाम की स्थिति न बने।

ऑनलाइन सूचना से आसान हुआ आयोजन

भंडारे और बड़े आयोजनों को लेकर प्रशासन ने इस बार व्यवस्था को और सरल बनाया है।

सरकारी नियमों के तहत अब आयोजकों को अपने भंडारे या धार्मिक कार्यक्रम की सूचना ऑनलाइन माध्यम से पुलिस को देनी होती है।

यदि किसी को फॉर्म भरने में परेशानी होती है, तो नजदीकी थाने में मौजूद अधिकारी उन्हें पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ी है और आयोजनों को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिल रही है।

भंडारों में दिखेगा स्वाद और सेवा का संगम

ज्येष्ठ मास के दौरान लखनऊ की एक खास पहचान भंडारों की परंपरा है। इस बार भी शहर के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं।

हत्या के प्रयास के मामले में लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर से अग्निवीर गिरफ्तार

अयोध्या (जीएनएस)।

वह अग्निवीर का प्रशिक्षण ले रहा था। सिंहाचवर कला का रहने वाला है। मामले का एक और आरोपी अमित गुप्ता उर्फ हंटर अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है।

थानाध्यक्ष हितेश कुमार ने बताया कि सिंहपुर खुर्द निवासी सुकई राजभर ने तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुकई का आरोप था कि उसका नाती सूरज राजभर 6 अक्तूबर 2025 को चाचा के साथ बाइक से बाजार से खीरा खरीदने गया था जहां पहले से घात लगा कर बैठे दारा चौधरी, अमित गुप्ता उर्फ हंटर सहित आठ आरोपियों ने तमंचे से उसे गोली मार दी। सूरज को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद वह ठीक हो सका।

हंटर पहले से ही अपनी पत्नी और सास की हत्या में नामजद है। दोनों की हत्या नगरा के बछईपुरा के छोटकापुरा में हुई थी। इस मामले में भी हंटर की तलाश चल रही है।

पुलिस के मुताबिक सूरज पर हमले के बाद से दोनों आरोपी भाग निकले थे। इसी बीच दारा चौधरी का अग्निवीर में चयन हो गया। वह प्रशिक्षण लेने लखनऊ चला गया।

सूचना मिलने के बाद उपनिरीक्षक अनिल यादव की अगुवाई में पुलिस की टीम शुक्रवार को लखनऊ गई और प्रशिक्षण से जुड़े सैन्य अफसरों को मामले की जानकारी दी। सैन्य अफसरों को भरोसे में लेने के बाद पुलिस ने उसे ट्रेनिंग सेंटर से ही गिरफ्तार कर लिया। अब दारा को बलिया लाया जा रहा है। शनिवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा।

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम बने समर्थ गुप्ता, गौरव दीक्षित को मिली स्टेशन निदेशक की जिम्मेदारी

(जीएनएस)।

लखनऊ। भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी समर्थ गुप्ता उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम बन गए हैं। उन्होंने गुरुवार को कार्यभार ग्रहण किया।

साथ ही सीनियर डीसीएम फ्रेट गौरव दीक्षित ने लखनऊ स्टेशन के निदेशक और इस पद पर रहे प्रशांत कुमार ने सीनियर डीसीएम फ्रेट की जिम्मेदारी संभाली है।

सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी के स्थानांतरण के साथ इस पद पर समर्थ गुप्ता को नियुक्त करने के आदेश बीती शुक्रवार को रेलवे बोर्ड ने दिए थे।

समर्थ गुप्ता वर्ष 2012 परीक्षा बैच के आइआरटीएस अधिकारी हैं। वह एरिया आफिसर आगरा कैंट, मंडल यातायात प्रबंधक टुंडला, वरिष्ठ यातायात प्रबंधक/फ्रेट आपरेशन सहित कई पदों पर सेवाएं दे चुके हैं।